

संख्या/ २३ / XXIV-3 / 2007/2(110)/05-

प्रेषक,

एस० के० माहेश्वरी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड देहरादून ।

शिक्षा अनुभाग-३ देहरादून दिनोंक २५ जनवरी, 2007

विषय: राजकीय इण्टर कालेज सीराखाल, रुद्रप्रयाग के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या नियोजन-४/40869/अधूरे भवन/2006-07 दिनोंक 15-11-2006 के कम में शासनादेश संख्या: 127/माध्यमिक/2001 दिनोंक 21-12-2001 एवं शासनादेश संख्या: 46/XXIV-3/2006 दिनोंक 25-3-2006 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय राजकीय इण्टर कालेज सीराखाल, रुद्रप्रयाग के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु अनुमोदित लागत रु० 206.68 लाख के सापेक्ष पूर्व स्वीकृत रु० 181.31 लाख को समायोजित करते हुए देय अवशेष सम्पूर्ण धनराशि रु० रु० 25.37 लाख (रूपये पच्चीस लाख रौंतीस हजार मात्र)की धनराशि को शासनादेश संख्या 233/ XXIV-3 / 2006 दिनोंक 27-4-2006 द्वारा प्रश्नगत योजना में आपके निवर्तन पर रखी गयी धनराशि रु० 367.00 लाख में से नियमानुसार व्यय करने की राहर्थ स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

- 1- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिल्पयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गयी हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।
- 2- कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानवित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी

2

होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य प्रारम्भ न किया जाये।

3— कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

4— एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त कार्य टेकअप किया जाये।

5— कार्य कराने से पूर्व समर्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रबलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

6— कार्य कराने से पूर्व स्थल का भलीभौंहि निरीक्षण लाना अधिकारियों एवं भूगर्वदेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाए।

7— आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाये।

8— निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेरिटंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पारी जानी वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाये।

(9)— निर्माण की गुणवत्ता के लिए संबंधित निर्माण ऐजेन्सी उत्तरदायी होगी। अनुमोदित लागत पर ही निर्माण कार्य को पूरा किया जाय। किसी भी दशा में आगणनों को पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा।

2— उपर्युक्त धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय और जहाँ आवश्यक हो, व्यय करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर यथा समय शासन तथा महालेखाकार को उपलब्ध करा दिया जाय। स्वीकृति की प्रत्याशा में अनानुमोदित व्यय कदापि न किया जाय।

3— इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-11 के अधीन लेखा शीर्षक 4202-शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर धूंजीगत परिव्यय -01-सामान्य

शिक्षा-202-माध्यमिक शिक्षा -आयोजनागत- 91-जिला योजना-
9102-राजकीय उमाओविद्यालयों /इंटर कालेजों -बालक/बालिका के
अवूरे भवनों के निर्माण हेतु एकमुश्त व्यवस्था -24 वृहत निर्माण कार्य
के नामे ढाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-
1495/वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/2006 दिनांक 02 जनवरी,
2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस० के० माहेश्वरी)

सचिव

संख्या: 23 (1)/ XXIV-3/2006 तददिनोंका।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी।
- 3- निजी सचिव, मा० शिक्षा मंत्री जी।
- 4- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- आयुक्त गढ़वाल मण्डल- पौड़ी।
- 6- मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल-पौड़ी।
- 7- बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय।
- 8- जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग।
- 9- कोषाधिकारी, रुद्रप्रयाग।
- 10- जिला शिक्षा अधिकारी, रुद्रप्रयाग।
- 11- वित्त विभाग /नियोजन प्रकोष्ठ।
- 12- कम्प्यूटर सेल(वित्त विभाग)
- 13- एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 14- संबंधित निर्माण ऐजेन्सी।
- 15 - गार्ड फाइल।

आझी से,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव

३